

ट्यूनीशिया में पावर ग्रैब

प्रलिम्स के लिये:

ट्यूनीशिया का भूगोल, इसके पड़ोसी देश और जलमार्ग

मेन्स के लिये:

संवधान में परिवर्तन का देश पर प्रभाव, सरकारी प्रणाली के प्रकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ट्यूनीशिया में एक नए [संवधान](#) को मंजूरी देने के लिये जनमत संग्रह किये जाने के बाद वरिध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे देश में फरि संसदरपति शासन लागू हो जाएगा।



वरिध प्रदर्शन:

- ट्यूनीशियाई मतदाताओं ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है जो देश को एक राष्ट्रपति शासन में बदल देगा, राष्ट्रपति कैस सैयद के एक-व्यक्ति शासन (जन्होंने नरिवाचति **संसद** को नलिंबति कर दिया और वर्ष 2021 में खुद को और अधिक शक्तियाँ प्रदान कीं) को यह संस्थागत रूप देगा, जन्होंने नरिवाचति संसद को नलिंबति कर दिया तथा पछिले साल खुद को और अधिक शक्तियाँ प्रदान कीं।
- प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि नया संविधान ट्यूनीशिया में स्थापित उस लोकतंत्र को समाप्त कर देगा जिसकी प्राप्ति वर्ष 2011 की **अरब स्प्रिंग** (जैसमीन) क्रांति के बाद हुई थी और देश को वापस एक सत्तावादी स्थिति में पहुँचा देगा।

अरब स्प्रिंग:

परिचय:

- अरब स्प्रिंग, **लोकतंत्र समर्थक वरिध और वदिरोह की लहर जो वर्ष 2010 और 2011 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में शुरू हुई** ने इस क्षेत्र के कुछ सत्तावादी शासनों को चुनौती दी।
- यह लहर तब शुरू हुई जब ट्यूनीशिया और मिस्र में वरिध प्रदर्शनों ने अन्य अरब देशों को इसी तरह के प्रयासों के लिये प्रेरित करते हुए त्वरित शासन को उखाड़ फेंका।
- वरिध आंदोलन हर देश में सफल नहीं रहे हैं, हालाँकि अपनी राजनीतिक और आर्थिक मांगों के लिये आंदोलन करने वाले प्रदर्शनकारियों को अक्सर उनके देशों के सुरक्षा बलों की हसिक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

ट्यूनीशिया:

- वर्ष 2011 में तानाशाही को लेकर हुए लोकप्रिय जन वरिध की घटना वाले देशों में ट्यूनीशिया एकमात्र ऐसा देश था जहाँ **लोकतंत्र** को एक सफल परिवर्तन के रूप में देखा गया।
- दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया में अरब स्प्रिंग का वरिध शुरू हुआ, जिससे ज़िन एल अबदिन बेन अली (वर्ष 1987 से सत्तारूढ़) के शासन का पतन हो गया।
 - इसे ट्यूनीशिया में **जैसमीन क्रांति** के रूप में भी जाना जाता था।
- जन वदिरोह के कारण बेन अली को देश छोड़कर भागना पड़ा।
 - शीघ्र ही वरिध अन्य **अरब देशों जैसे- मिस्र, लीबिया, बहरीन, यमन और सीरिया में फैल गया।**

मिस्र:

- जबकि प्रदर्शनकारियों ने मिस्र में होसनी मुबारक की 30 साल की तानाशाही को समाप्त कर दिया जिससे उस देश में क्रांति लंबे समय तक नहीं चली।
- वर्ष 2013 में सेना ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की नरिवाचति सरकार को गरिने के लिये सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।

लीबिया:

- लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ वरिध **गृहयुद्ध** में बदल गया, जिसमें **उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO)** द्वारा सैन्य हस्तक्षेप देखा गया।
 - नाटो के हस्तक्षेप ने गद्दाफी शासन को गरि दिया (लीबिया के नेता की बाद में हत्या कर दी गई), लेकिन देश अराजकता और तानाशाही में बदल गया, जो आज भी इस समस्या से परेशान है।

अन्य देश:

- सुन्नी राजशाही द्वारा शासित शिया बहुल देश **बहरीन** में पड़ोसी सऊदी अरब ने **मनामा के परल सक्वायर** में वरिध प्रदर्शनों को कुचलने के लिये सेना भेजी।
- यमन में राष्ट्रपति अली अबदुल्ला सालेह को सत्ता छोड़नी पड़ी, लेकिन देश गृहयुद्ध में बदल गया, जिससे **शिया हौथी वदिरोहियों** का उदय हुआ और राजधानी **सना पर** अब उसका नयितरण है।
- **सीरिया में** वरिध छद्म गृहयुद्ध में बदल गया, जिसमें राष्ट्रपति बशार अल-असद के प्रतद्विंद्वियों ने अपने दुश्मनों का समर्थन किया और हज़िबुल्लाह, ईरान एवं रूस के सहयोगियों ने शासन का समर्थन किया।

ट्यूनीशिया में राजनीतिक संकट का कारण:

मौजूदा तंत्र:

- वर्ष 2014 के संविधान ने **मिश्रित संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की स्थापना की।**
 - राष्ट्रपति और संसद दोनों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता था।
 - राष्ट्रपति को सैन्य और वदिशी मामलों की देख-रेख करनी थी, जबकि अधिकांश सांसदों के समर्थन से चुने गए प्रधानमंत्री को शासन के दिनि-प्रतदिनि के मामलों का प्रभार सौंपा गया था।

ट्यूनीशिया में समस्याएँ:

- वर्ष 2011 से वर्ष 2021 के बीच देश में नौ सरकारें बनीं।
 - लोकतांत्रिक चुनावों में इस्लामवादी एन्नाहदा पार्टी, जिसका अखलि-इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड आंदोलन से वैचारिक संबंध है, देश में एक मुख्य राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी, इसने धर्मनरिपेक्ष वर्गों को परेशान किया जिस कारण राजनीति अस्थिरता की स्थिति देखी गई।
- इसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब स्थिति में थी और **COVID-19** संकट ने इसे और खराब कर दिया।
 - ट्यूनीशिया में COVID मृत्यु दर दुनिया में सबसे अधिक है।
- बढ़ते आर्थिक और स्वास्थ्य संकट के बीच पछिले वर्ष जुलाई में सरकार के खिलाफ वरिध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
 - प्रदर्शनकारियों ने सत्ताधारी दल एन्नाहदा के कार्यालयों पर धावा बोल दिया।

संविधान में बदलाव:

- अशांतिको रोकने के लिये सईद ने एन्नाहदा समर्थति प्रधानमंत्री हकैम मेचचि को बरखास्त कर दिया और संसद को नलिंबति कर दिया जसिसे देश में एक संवैधानिकि संकट की स्थति उत्पन्न हो गई ।
- वर्ष 2014 के संवधान के तहत ऐसे संकटों का नपिटारा एक संवैधानिकि न्यायालय द्वारा कथिा जाना चाहयि, लेकनि अभी तक न्यायालय का गठन नहीं हुआ ।
 - इसने राष्ट्रपतिको फरमानों द्वारा देश पर शासन करने की खुली छूट दी ।
 - उन्होंने आपातकाल की स्थति घोषति कर दी ।
 - सरकार चलाने के लयि एक प्रधानमंत्री नयुक्त कथिा ।
 - इस वर्ष की शुरुआत में संसद को भंग कर दिया और साथ ही खुद को और अधिक शक्तयिँ परदान करते हुए संवधान को नया रूप दिया ।

संवधान में नए बदलाव:

- हालाँकि इसने वर्ष 2014 के संवधान द्वारा गारंटीकृत अधिकांश व्यक्तगित स्वतंत्रता को बरकरार रखा है, नया चार्टर संसद की शक्तयिँ को कम करते हुए देश को राष्ट्रपति प्रणाली में वापस ले जाने का प्रयास है ।
 - राष्ट्रपतिके पास अंतिम अधिकार होगा:
 - सरकार बनाने का
 - मंत्रयिँ को नामति करने का (संसद की मंजूरी के बनिा)
 - न्यायाधीशों की नयुक्ति करने
 - वधानसभा को सीधे वधायिका के रूप में प्रस्तुत करने का
- उपर्युक्त सभी परिवर्तन सांसदों के लयि राष्ट्रपतिको पद से हटाना व्यावहारिक रूप से असंभव बना देंगे ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. हाल ही में, लोगों के वदिरोह की एक शृंखला जसि 'अरब स्प्रिंग' कहा जाता है, मूल रूप में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? (2014)

- मसिर
- लेबनान
- सीरयिा
- ट्यूनीशयिा

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- अरब स्प्रिंग दसिंबर 2010 में शुरु हुआ जब एक ट्यूनीशयिाई फुटपाथ वकिरेता मोहम्मद बउज़िज़ी (Mohammed Bouaziz) ने परमटि प्राप्त करने में वफिल होने पर पुलिस द्वारा उसके सब्जी स्टैंड को मनमाने ढंग से ज़ब्त करने का वरिध करते हुए खुद को आग लगा ली । ट्यूनीशयिा में तथाकथति जैस्मनि क्रांति में बउज़िज़ी के बलदान ने उत्प्रेरक के रूप में कार्य कथिा ।
- अरब के अन्य देशों के कार्यकर्त्ता ट्यूनीशयिा में शासन परिवर्तन से प्रेरति थे और उन्होंने अपने ही राष्ट्रों में समान सत्तावादी सरकारों का वरिध करना शुरु कर दिया । अंततः ट्यूनीशयिा में पहला लोकतांत्रिकि संसदीय चुनाव अक्टूबर 2011 में संपन्न हुआ था ।
- वर्ष 2011 की शुरुआत में इसे अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाने लगा था तथा वरिध, वदिरोह एवं अशांति की यह लहर, जो उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक सीमति थी, अरबी भाषी देशों में भी फैल गई । लोकतंत्र समर्थक आंदोलन, जो सोशल मीडयिा के कारण तेज़ी से फैल गया था, इसने ट्यूनीशयिा, मसिर, लीबयिा तथा यमन की सरकारों को गिरा दिया ।
- हालाँकि कुछ देशों में ये आंदोलन पूर्ण पैमाने पर गृहयुद्ध में बदल गए, जैसा कलिबयिा, सीरयिा और यमन जैसे देशों में देखा जा सकता है ।

अतः वकिलप (d) सही है ।

स्रोत: द हिंदू